concessional duty for export production, special arrangements for duty free import of raw materials, ensuring increased availability of export credit etc. Recently, the Government have annonced specific measures for boosting cotton yarn exports which include delinking of cotton yarn exports from hank yarn obligation; greater operational flexibility to 100% EOUs producing cotton yarn by way of relaxation of count/domestic cotton use restrictions etc.

Revival of sick Textile Mills

308. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new textile mills in the country during the Ninth Plan;

(b) if so, the details thereof, Statewise, particularly in Gujarat; and

(c) the details of funds provided by Government to the State Governments for the revival of sick textiles mills during the current year and the Ninth Plan period, State-wise?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) There is no proposal before the Government to set up a new Textile mill in any part of the Country.

(c) Government of India does not provide funds to the State Governments for revival of sick textile mills.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर बकाया राशि

309.**श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को समय-समय पर कपास की खरीद करने के लिए गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कपास संघ को कुछ बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों की सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस बकाया राशि का सीधा भुगतान किए जाने के संसबंध में प्रतिवदेन प्रेषित किया है;और

(घ) यदि हां,तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री(श्री काशीराम राणा): (क) और(ख) अगस्त,1998 तक की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी.द्वारा गुजरात राज्य कपास सहकारी समिति को कपास की देय बकाया राशि 14.81 करोड़ रूपए है। इसके अतिरिक्त 30.4.1998 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राजय कपास सहकारी समिति और मध्य प्रदेश बीज निगम को क्रमश: 2.78 लाख रूपए और 1.93 लाख रूपए की राशि भी बकाया हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए है । तथापि,सरकार को उपर्युक्त समितियों के बारे में इस आशय की जानकारी है कि वे बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए एन.टी.सी.को प्रतिवेदन कर रही है । चूंकि कपास उधार पर खरीदी जाती है इसलिए किसी भी समय कुछ बकाया राशि का होना स्वाभाविक है। कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन.टी.सी.ऐसी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है । एन.टी.सी.से ऐसी अपेक्षा है कि निधियों के उपलब्ध होने पर बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा।

Textile Mill Project

310. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether various State Governments in consultation with Textile Unions have presented any project report named as Textile Mill Project to make provision of 150 crore rupees in the current budget to make these textile mills financially viable and for reviving them;

(b) if so, the details thereof, Statewise;

(c) whether this project has been cleared;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the steps taken/being taken for the revival of these mills?